RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 351
दि. 24.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल-तमिलनाडु में लोकतंत्र का उत्सव: रिकॉर्ड वोटिंग ने बदली सियासी धार, परिणामों पर टिकी देश की नजर

कोलकाता/चेन्नई से आई खबर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत जनता की भागीदारी में निहित है। West Bengal और Tamil Nadu में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उसने न केवल पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी नए संकेत छोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल में जहां 91.40 प्रतिशत की ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज की गई, वहीं तमिलनाडु में भी 84.35 प्रतिशत मतदान ने 2011 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उस भरोसे और जागरूकता का प्रतीक हैं, जो देश के मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति रखते हैं।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 16 जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ, जहां 294 सदस्यीय विधानसभा की 152 सीटों पर 1,478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 167 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो इस चुनाव को और अधिक प्रतिनिधिक बनाते हैं। शाम पांच बजे तक 3.60 करोड़ मतदाताओं में से 91.40 प्रतिशत ने मतदान किया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया कीर्तिमान है। दक्षिण दिनाजपुर जिला 93.12 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था बनी हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मतदान प्रतिशत में आई भारी बढ़ोतरी के पीछे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' यानी एसआईआर प्रक्रिया की बड़ी भूमिका रही है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें 91 लाख से अधिक नाम हटाए गए। इससे मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन बनी, जिसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ा। इसके अलावा राजनीतिक दलों की सक्रियता, चुनावी माहौल और मतदाताओं के बीच बढ़ी जागरूकता भी इस रिकॉर्ड वोटिंग के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

वहीं Tamil Nadu में भी मतदान का उत्साह कम नहीं रहा। यहां एक ही चरण में 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए और पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करूर जिला 89.32 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा, जबकि सेलम में 88.02 प्रतिशत और इरोड में 87.59 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि मदुरै (77.89%) और थूथुकुडी (77.56%) में अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज किया गया, लेकिन कुल मिलाकर राज्य में वोटिंग का प्रतिशत बेहद उत्साहजनक रहा।

मतदान समाप्त होने के बाद देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त Gyanesh Kumar ने दोनों राज्यों के मतदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया और हर मतदाता को सलाम किया।

इस भारी मतदान ने राजनीतिक दलों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर भी तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में Bharatiya Janata Party और All India Trinamool Congress दोनों ही इसे अपनी-अपनी जीत का संकेत मान रहे हैं। भाजपा का दावा है कि यह रिकॉर्ड वोटिंग राज्य में बदलाव की लहर का संकेत है, जबकि टीएमसी इसे Mamata Banerjee सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोशल मीडिया के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की कि बंगाल में बदलाव का समय आ गया है, वहीं टीएमसी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह समर्थन उनके शासन के पक्ष में है, न कि उसके खिलाफ।

अगर पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। उस चुनाव में वाम दलों और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और वे खाता तक नहीं खोल पाए थे। वहीं Tamil Nadu में भी 2021 के चुनावों में Dravida Munnetra Kazhagam के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके के 10 साल के शासन को समाप्त कर सत्ता में वापसी की थी। डीएमके ने अकेले 133 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जो उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

इस बार के चुनावों में रिकॉर्ड मतदान ने यह संकेत जरूर दिया है कि जनता बदलाव या स्थिरता, किसी न किसी स्पष्ट दिशा में निर्णय लेने के मूड में है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी, लेकिन इतना तय है कि परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं।

फिलहाल, दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए मतदान के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी हैं। यह परिणाम न केवल राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। भारी मतदान ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

मतदान के बीच हिंसा की छाया: बीरभूम में सीआरपीएफ पर पथराव, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच जहां एक ओर रिकॉर्ड मतदान ने लोकतंत्र के प्रति जनता के उत्साह को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों से हिंसा की खबरों ने चिंता भी बढ़ा दी है। West Bengal के बीरभूम जिले में स्थित दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के खैरासोल घुमर गांव में मतदान के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए, जब Central Reserve Police Force (सीआरपीएफ) के जवानों पर स्थानीय लोगों द्वारा पथराव किया गया। इस घटना ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी और सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल सक्रिय होना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। Central Reserve Police Force के जवान नियमित गश्त और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अचानक कुछ लोगों की भीड़ ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। यह हमला अचानक और बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के हुआ, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, जवानों ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की और किसी बड़े टकराव से बचने का प्रयास किया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की आगे की हिंसा को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा और हर हाल में शांति बनाए रखी जाएगी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस पथराव के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर चुनावी हिंसा के उस पुराने मुद्दे को सामने ला दिया है, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में समय-समय पर देखने को मिलता रहा है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग और प्रशासन ने पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।

चुनाव आयोग ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मतदाताओं को बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।

हालांकि इस हिंसक घटना के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने वोट डाले। यह दर्शाता है कि कुछ isolated घटनाओं के बावजूद जनता का लोकतंत्र में विश्वास कायम है।

फिलहाल, बीरभूम के इस इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। आने वाले चरणों के मतदान को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल तैनात करने और निगरानी को और सख्त करने का फैसला किया है। इस घटना ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता और सख्ती दोनों जरूरी हैं।

फ्रांस से भारत के रिश्तों को नई उड़ान: अब बिना ट्रांजिट वीजा के आसान होगा सफर, यात्रियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली से आई एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खबर ने भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को और अधिक सरल बना दिया है। France ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने हवाई अड्डों पर ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिससे अब भारत से यूरोप या अन्य देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। Ministry of External Affairs ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत-फ्रांस संबंधों में एक सकारात्मक और व्यावहारिक कदम बताया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने जानकारी दी कि यह नई व्यवस्था 10 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है। इसके तहत भारतीय नागरिक अब France के हवाई अड्डों से बिना ट्रांजिट वीजा के यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते वे केवल एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र में ही रहें और देश में प्रवेश न करें। यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है, जो यूरोप, अमेरिका या अन्य देशों के लिए फ्रांस के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं।

यह निर्णय फरवरी 2026 में Narendra Modi और Emmanuel Macron के बीच हुई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक का परिणाम माना जा रहा है। उस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ट्रांजिट वीजा में यह छूट उसी दिशा में उठाया गया एक व्यावहारिक कदम है, जो आम नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर आसान बनाता है।

अब तक भारतीय यात्रियों को France के हवाई अड्डों पर ट्रांजिट के लिए भी वीजा लेना पड़ता था, जिससे न केवल समय और पैसे की अतिरिक्त लागत आती थी, बल्कि यात्रा की योजना बनाना भी जटिल हो जाता था। खासकर छात्रों, बिजनेस यात्रियों और पर्यटकों के लिए यह एक बड़ी बाधा थी। नए नियम के लागू होने के बाद अब इन सभी वर्गों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सहज और किफायती हो सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत और यूरोप के बीच हवाई यातायात में भी वृद्धि हो सकती है। फ्रांस के प्रमुख एयरपोर्ट, जैसे पेरिस का चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, पहले से ही एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट हब है। अब जब भारतीय यात्रियों के लिए ट्रांजिट वीजा की बाध्यता हट गई है, तो अधिक लोग फ्रांस के रास्ते यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। इससे न केवल एयरलाइंस को फायदा होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापारिक संपर्क भी मजबूत होंगे।

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल एयर ट्रांजिट के लिए है। यदि कोई यात्री फ्रांस में प्रवेश करना चाहता है या एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहता है, तो उसे पहले की तरह नियमित वीजा लेना होगा। इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

इस घोषणा के साथ ही विदेश मंत्रालय ने अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत का रुख स्पष्ट किया। Japan की नई रक्षा नीति को लेकर भारत ने कहा कि वह अपने साझेदार देशों के साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग करता रहेगा। वहीं खाड़ी देशों में फंसे भारतीय जहाजों के मुद्दे पर मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों तथा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, फ्रांस द्वारा दी गई यह ट्रांजिट वीजा छूट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। यह कदम उन हजारों भारतीय यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, जो हर साल अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं। आने वाले समय में ऐसे और फैसलों की उम्मीद की जा सकती है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की कनेक्टिविटी और प्रभाव को और मजबूत करेंगे।

भरूच के औद्योगिक इलाके में बड़ा हादसा: केमिकल फैक्ट्री में धमाका, भीषण आग से कई मजदूर झुलसे

नई दिल्ली/भरूच से आई खबर ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। Gujarat के भरूच जिले स्थित झगड़िया GIDC क्षेत्र में 'मेट्रोपॉलिटन एक्सीकेम' कंपनी के प्लांट में हुए जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फैक्ट्री परिसर में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के गांवों तक लोग सहम गए और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उस वक्त प्लांट में कई मजदूर काम कर रहे थे और विस्फोट के बाद आग तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते पूरा यूनिट धुएं और लपटों में घिर गया, जिससे मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, लेकिन कुछ मजदूर आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए।

घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए Jayaben Modi Hospital ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही झगड़िया, अंकलेश्वर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे उसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। दमकलकर्मी फोम और पानी का इस्तेमाल कर आग बुझाने में जुटे हैं और कई घंटों से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। आसपास की अन्य इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि आग फैलने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

प्रशासन के अनुसार, प्राथमिकता दो स्तरों पर काम करने की है—पहला, आग को पूरी तरह काबू में लाना और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्लांट के अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा न रह जाए। इसके लिए बचाव दलों द्वारा प्लांट के विभिन्न हिस्सों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही, आसपास के क्षेत्र को खाली करवाने और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए पुलिस ने घेरा बना दिया है।

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर गैस रिसाव या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए औद्योगिक सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की तैयारी कर रही है। हादसे के बाद संबंधित फैक्ट्री प्रबंधन से भी जवाब मांगा जाएगा कि सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक किया गया था।

झगड़िया GIDC क्षेत्र पहले भी ऐसे हादसों को लेकर चर्चा में रहा है, जहां केमिकल इकाइयों में सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस ताजा घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि खतरनाक रसायनों के साथ काम करने वाली फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कितना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और कड़े कदम उठाने की बात भी कही जा रही है।

फिलहाल, पूरे इलाके में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित स्थिति बनी हुई है। दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और प्रशासन हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यह हादसा न केवल औद्योगिक सुरक्षा की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि विकास के साथ सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है।

संपादकीय

झुलसती जिंदगी

एक वैश्विक संस्था एक्यूआई.इन के हालिया आंकड़ों से यह परेशान करने वाली तस्वीर उभरी है कि दुनिया के सबसे गर्म बीस शहरों में 19 भारत के हैं। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान का मुख्य कारक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकारों व आम नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में है। घटता वनों का दायरा और हमारी जीवनशैली में बदलाव से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ते तापमान का एक कारक बन रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों तक बारिश के बाद लोग अप्रैल माह में भी ठंड का अनुभव कर रहे थे। उसके कुछ ही दिन बाद तुरंत लू चलने लगी। यह अचानक होने वाला मौसमी बदलाव हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। तमाम लोग अचानक मौसमी बदलाव से उत्पन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का सबसे ज्यादा 44.4 तापमान दर्ज किया जाना गंभीर स्थिति को दर्शाता है। चिंता की बात यह है कि गर्मी सामान्य सीमाओं को पार करके आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग चेता रहा है कि देश के कई इलाकों में आगामी दिनों में लू की स्थिति बनी रहेगी। कई जगह पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। दरअसल, मौसम विभाग का मानक है कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो इसे लू चलना कहा जाता है। फिक्र की बात यह है कि अप्रैल के चौथे सप्ताह में ही देश के कई शहर हीटवेव की सीमा से आगे बढ़ गए हैं। देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्य इस तपिश का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पहली बार मध्यप्रदेश में रात को हीटवेव चलने की चेतावनी दी गई है। गर्मी का आलम यह है कि देश के कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली के स्कूलों में एक समय अवधि घंटी बजाकर छात्रों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि वे पानी पीकर गर्मी की चुनौती का मुकाबला करें।

गर्मी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देश के तमाम राज्यों में जीवन रक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। कई जगह श्रमिकों के दिन में कुछ घंटों में काम करने पर रोक लगायी गई है। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का समय बदला गया है। तमाम शहरों में लू के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कई जगह ट्रैफिक सिग्नल बंद किए गए ताकि लोगों को चौराहों पर धूप में खड़ा न रहना पड़े। सड़कों, बस स्टेशनों तथा रेलवे स्टेशनों में पानी की फुहार के जरिये गर्मी से राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताजमहल देखने पहुंचे कई पर्यटकों के बेहोश होने के समाचार हैं। गर्मी के चलते राजस्थान के कई पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में गिरावट के संकेत हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस सप्ताह दिल्ली में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। बहरहाल, इन तमाम चिंताओं के बीच प्रश्न यह है कि अप्रत्याशित गर्मी क्यों बढ़ रही है। दरअसल, अप्रैल माह में प्री-मानसून हीट पीरियड के चलते जमीन पर पड़ने वाली तेज धूप गर्मी का एक कारण है। बताया जाता है कि हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फबारी भी गर्मी बढ़ने का एक कारक है। वहीं समुद्री सतह के गर्म होने से भी गर्मी का असर तेज हो रहा है। फलतः वातावरण में ठंडक लाने वाली हवाएं व सिस्टम कमजोर होने से, वे ही गर्मी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं शुष्क हवाएं बादल बनने में अवरोध पैदा करके बारिश की संभावना को कम कर दे रही हैं। निश्चित रूप से यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भी देन है। यह वर्तमान ही नहीं, भविष्य में भी और तापमान बढ़ने की चिंता भी दर्शाता है। आशंका है कि भविष्य में तापमान में तीव्रता और बार-बार हीटवेव चलने की स्थिति बढ़ सकती है। हाल-फिलहाल मानसून से पहले की फुहारों के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्दी बारिश न होने से इस माह के बाकी दिनों में भी हमें गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

कच्ची पर्ची पर रोक से किसानों को राहत की पहल

> “ हरियाणा की कृषि मंडियों में अनेक आढ़ती तय नियमों का उल्लंघन कर किसानों को अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देते रहे व बीज-उर्वरक-कृषि रसायन आदि बेचते रहे हैं। इस संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर अमल के बाद इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कृषि निवेश व्यापार पर प्रतिबंध लगा है। जिससे वर्षों से जारी किसानों के साथ अन्याय पर रोक लगेगी।

कृषि लागत और मूल्य आयोग और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की विभिन्न रिपोट्र्स के अनुसार, देश में अधिकांश समय, फसल उपज की कीमतें औसतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर और समर्थन मूल्य से नीचे बनी रहीं और बिचौलिए आढ़तियों द्वारा शोषण के कारण कृषि उपज वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा बेहद कम बना हुआ है। यह हिस्सा फसल और बाजार के आधार पर 28 से 78 प्रतिशत के बीच है। ये चिंताजनक आंकड़े मंडी व्यवस्था में मूलभूत नीतिगत सुधारों की आवश्यकता दर्शाते हैं।

हरियाणा की कृषि उपज मंडियों में बिचौलिए आढ़तियों के शोषण से किसानों को मुक्त करने के लिए, लागू किए गए फसल बिक्री पर धनराशि किसान के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करने जैसे नीतिगत सुधारों के सकारात्मक नतीजे मिले हैं। फसल बिक्री से किसानों को मिलने वाली राशि पर आढ़तियों की पकड़ ढीली हुई है।

आढ़तियों की कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। जिसके चलते 1 अप्रैल 2026 को प्रदेश की मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बन्द करने और उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद कानूनी रसीद जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने के आदेश जारी किए। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार, अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगने से, प्रदेश के किसानों को 30-40 प्रतिशत यानि गेहूं-धान फसल चक्र में 25-30 हजार रुपये प्रति एकड़ ज्यादा सालाना लाभ होगा।

इस फैसले को किसान हित में महत्वपूर्ण कृषि विपणन सुधार माना जा रहा है।

हरियाणा की मंडियों में लगभग 16 करोड़ क्विंटल खाद्यान्न, 1.5 करोड़ क्विंटल तिलहन, एक करोड़ क्विंटल दलहन और 12-15 लाख बेल कपास आदि फसल उपज का वार्षिक विपणन होता है । इन सबका मौजूदा समर्थन मूल्य लगभग 70,000 करोड़ रुपये वार्षिक है। गौरतलब है कि मार्च-2022 से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में 114 मुख्य मंडियों और कुल 376 उप-मंडियों/खरीद केन्द्रों का विशाल नेटवर्क है, जिसमें लगभग 40 हजार आढ़ती कार्यरत हैं। इन्हें विभिन्न फसलों की बिक्री पर 2 से 2.5 प्रतिशत कमीशन (आढ़त) मिलता है। जो लगभग 1400 करोड़ रुपये वार्षिक बनता है। ऐसे में प्रत्येक आढ़ती को औसत 3-4 लाख रुपये वार्षिक आढ़त बनती है। जो प्रदेश में कुशल श्रमिक के वार्षिक वेतन से भी कम है।

निस्संदेह, प्रदेश की कृषि मंडियों में आढ़तियों की संख्या जरूरत से ज्यादा होने के कारण, वैध आढ़त का धंधा लाभप्रद नहीं रहा। ऐसे में कुछ आढ़तियों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कच्ची पर्ची व्यवस्था, मनी लॉन्ड्रिंग व नकली बीज-खाद-दवाई बेचने जैसे अवैध धन्धे अपना लिये। वहीं तन्त्र के कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत से किसानों का शोषण और सरकारी धन का गबन करते रहे हैं। आढ़तियों ने कृषि उपज विपणन कमेटी एक्ट-1961 रूल्स-1962 का उल्लंघन कर कच्ची पर्ची सिस्टम से वर्ष-2025 में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के धान घोटाले में सरकारी धन के गबन को अंजाम दिया। जिसकी राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर जांच कर रही है। जबकि किसान संगठन और राजनीतिक दलों के नेता आढ़तियों द्वारा किये गये कथित घोटाले की विस्तृत जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग कर रहे हैं। कथित तौर पर यह सरकारी धन आढ़तियों के जरिये काले धन में प्रवर्तित किया गया।

हरियाणा राज्य कृषि उपज विपणन कमेटी अधिनियम के तहत राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड मंडियों में कृषि उपज की खरीद-फरोख्त करने के लिए कमीशन एजेंट को आढ़त का लाइसेंस देता है जो सरकार के दिशानिर्देश अनुसार व्यापार करने को कानूनी तौर पर बाध्य हैं। लेकिन बिचौलिए आढ़ती मिलीभगत से तय नियमों का उल्लंघन करके मनी लॉन्ड्रिंग धंधे (किसानों को अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देना आदि) में लगे हुए हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए इन अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जब्त करने और इनमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, मजबूर कर्जमंद किसानों को आढ़ती बिना लाइसेंस लिए ही कथित नकली बीज-उर्वरक- कृषि रसायन आदि बेचकर, किसान और खेती को गंभीर नुकसान कर रहे हैं। आढ़तियों की अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और कृषि निवेश व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने से हरियाणा की मंडियों में वर्षों से हो रहे करीब दस हजार करोड़ रुपए वार्षिक के किसानों के शोषण और सरकारी धन के गबन पर भी लगाम लग सकेगी और खेती टिकाऊ बनेगी। जिससे कृषि विपणन में क्रान्तिकारी सुधार और लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आढ़तियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग व धोखाधड़ी पर नकेल कसेगी।

प्रेरणा

अडिग कर्तव्यबोध ही महानता की पहचान

Immanuel Kant जर्मनी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे और उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सिद्धांत केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी उतारे जाने चाहिए। वे समय के इतने पाबंद और कर्तव्य के इतने निष्ठावान थे कि उनकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह नियमित मानी जाती थी। उनके लिए कर्तव्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नैतिक धर्म था, जिसे किसी भी परिस्थिति में निभाना आवश्यक है। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना इस सत्य को अत्यंत गहराई से उजागर करती है।

एक दिन सुबह से ही तेज़ बर्फबारी हो रही थी। वातावरण में कड़ाके की ठंड थी और रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढक चुके थे। सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है। ऐसे में उनके नौकर ने उनसे विनम्रता से कहा कि आज कॉलेज जाना उचित नहीं होगा। उसने तर्क दिया कि इतनी भयंकर ठंड और बर्फ के कारण कोई भी छात्र कक्षा में नहीं आएगा, इसलिए आज घर पर ही रुक जाना समझदारी होगी। यह सलाह व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल सही थी और कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता था।

लेकिन कांट का दृष्टिकोण साधारण नहीं था। उन्होंने नौकर की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि उनका कर्तव्य है कॉलेज जाना और पढ़ाना, और वे इसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि छात्र आएंगे या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण था कि वे स्वयं अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी।

वे अपने निर्धारित समय पर तैयार हुए और बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए कॉलेज के लिए निकल पड़े। हर कदम पर ठंड और कठिनाई उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। जब वे कॉलेज पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी छात्र उपस्थित नहीं है। कक्षा खाली थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही स्थिति थी, जिसकी संभावना उनके नौकर ने पहले ही व्यक्त की थी।

इसके बावजूद कांट ने निराशा या खेद प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने निर्धारित समय तक कक्षा में बैठकर अपना कर्तव्य निभाया, मानो छात्र उपस्थित हों। उनके लिए कर्तव्य का अर्थ केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना था। कुछ समय बाद वे शांत मन से घर लौट आए, जैसे उन्होंने एक सामान्य दिन की तरह अपना कार्य पूरा किया हो। घर पहुंचने पर नौकर ने मुस्कराते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था कि आज जाना व्यर्थ रहेगा। इस पर कांट ने जो उत्तर दिया, वह उनके जीवन दर्शन का सार था। उन्होंने कहा कि उनका कॉलेज जाना व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र को यह पता चलेगा कि उनका शिक्षक इतने खराब मौसम में भी अपने कर्तव्य के प्रति इतना समर्पित है, तो यह उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा और वह भी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर बनेगा।

इस घटना में छिपा संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में अधिकांश लोग अपने कार्यों को लाभ और परिणाम के आधार पर आंकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि किसी कार्य से उन्हें कोई तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, तो वे उसे करने से बचते हैं। लेकिन कांट का विचार इससे बिल्कुल भिन्न था। उनके लिए कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा लक्ष्य था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कर्तव्यनिष्ठ आचरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। यह उसे अनुशासित, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो वह अपने भीतर एक आत्मसंतोष का अनुभव करता है, जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यही आत्मसंतोष उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

कांट के विचारों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने आचरण से छात्रों को प्रेरित करना भी है। एक कर्मचारी का कर्तव्य केवल काम करना नहीं, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करना है।

आज के युग में, जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहां कर्तव्यनिष्ठा का महत्व और भी अधिक हो गया है। लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर देते हैं, जिससे समाज में असंतुलन और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ऐसे समय में कांट जैसे महान विचारकों की शिक्षाएं हमें सही दिशा दिखाती हैं और यह याद दिलाती हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी में निहित है।

यह भी समझना आवश्यक है कि कर्तव्य का पालन केवल बाहरी नियमों के कारण नहीं, बल्कि भीतर की नैतिक भावना से होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपना धर्म मानकर निभाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट होता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता, बल्कि हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करता है।

कांट की यह प्रेरणादायक घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन उनसे घबराकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना सही नहीं है। बल्कि इन्हीं कठिन परिस्थितियों में हमारे चरित्र की असली परीक्षा होती है और यही हमें मजबूत बनाती हैं। अंततः, कर्तव्यनिष्ठ आचरण एक ऐसा गुण है, जो व्यक्ति को महान बनाता है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कर्तव्य के प्रति अडिग रहना ही सच्ची महानता की पहचान है और यही हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है।

कोल्ड ड्रिंक से केला तक No Entry, भारत से सामान लाने से अब नेपाल की बालेन शाह सरकार को क्या परेशानी?

एक मां अपने बच्चों के लिए चिप्स का एक पैकेट लेकर बॉर्डर क्रॉस कर रही है। भारत से नेपाल जा रही है और बॉर्डर पर खड़े आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान उसे रोक लेते हैं। कहते हैं यह पैकेट 100 से ऊपर का है। कस्टम ड्यूटी लगेगी। वो महिला पूछती है बच्चों के लिए चिप्स का पैकेट भी अब स्मगलिंग है। यह सीन किसी फिल्म का नहीं है। यह एक रियल वीडियो है जो नेपाल के नेपालगंज बॉर्डर से आया है और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस एक वीडियो ने एक ऐसे रूल पर स्पॉट लाइट डाल दी है जिसने नेपाल के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। तो आज इस पूरे मामले का एमआरआई स्कैन करते हैं। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। दोनों मुल्क के नेताओं को अगर भारत-नेपाल संबंध पर दो शब्द बोलना पड़े तो, भाषण ही इसी मुहावरे से शुरु होता है। लेकिन रोटी-बेटी के इस मुहावरे पर धीरे-धीरे ग्रहण लगता जा रहा है और भारत-नेपाल दोस्ती में दरार पड़ती नजर आ रही है। नेपाल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव जारी किया है जिसके तहत अगर कोई नेपाली नागरिक भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल में एंटर करता है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अब 100 नेपाली रुपए का मतलब समझिए। इंडियन करेंसी में यह करीब 62 से 63 बनते हैं। मतलब आप इंडिया से 63 का सामान भी लेकर गए तो आपको बॉर्डर पर रुक कर ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अब यह रूल नया नहीं है। नेपाल के कस्टम एक्ट में यह प्रोविजन पहले से था। लेकिन सालों से इसे कोई सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं करता था। बॉर्डर एरियाज में लोग इंडिया से छोटा-मोटा सामान लाते थे। दवाइयां, कपड़े, राशन, सब्जी और कोई उन्हें नहीं रोकता था। लेकिन अब नेपाल की नई गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक्टली इनफोर्स करने का फैसला किया है और इनफोर्समेंट भी ऐसा कि बॉर्डर पर माहौल ही बदल गया है। नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ के जवान अब बॉर्डर पॉइंट्स पर लाउडस्कर लगाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यह 100 से ऊपर का कोई भी सामान डिक्लेअ करना होगा। झापा से लेकर कंचनपुर तक, पूर्व से पश्चिम तक हर कस्टम पॉइंट पर क्रैकडाउन चल रहा है। लोगों के बैग खोले जा रहे हैं। साइकिल पर आने वाले लोगों का सामान चेक हो रहा है। लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। कस्टम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नेपाल पुलिस और एपीएफ की जॉइंट मॉनिटरी टीमें बनाई गई हैं। नेपाल के कस्टम अधिकारी और बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी इस पार से उस पार जाने वाले लोगों के झोले और थैलियां चेक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ अब यह चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि केला से कोल्ड ड्रिंक तक अपना भारत से नेपाल ले जाने की इजाजत नहीं है। तस्वीरों में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात नेपाली पुलिस के जवान सख्ती से चेकिंग में जुटे हैं और उन्हें जो चीज भी रोकनी होती है उसे निकाल दे रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है नेपाल सरकार की नई बालन शाह सरकार के आदेश पर जिसके तहत नई नीति सीमा शुल्क के मुताबिक अब 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर 5% से लेकर 80% तक शुल्क सख्ती से वसूला जाएगा। भारत और नेपाल के बीच करीब 10715 किमी लंबी ओपन बॉर्डर है। 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। इस रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मतलब खाने और शादियों के जरिए दोनों देशों के लोग इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर है। जमीन पर नहीं है। नेपाल पांच भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इस ओपन बॉर्डर की वजह से नेपाल के बॉर्डर एरियाज के लोग दशकों से इंडिया के बाजारों पर डिपेंडेंट रहे हैं। खासकर मधेश प्रदेश के आठ जिलों में जो सीधे इंडिया की सीमा से लगते हैं। वहां के लोग इंडिया से दवाइयां, कपड़े, साड़ी, धोती, बिस्किट, सीमेंट, मसाले, सब्जी, दूध सब कुछ खरीद रहे हैं। इसका सीधा असर सीमावर्ती भारतीय बाजारों और नेपाली उपभोक्ताओं पर पड़ा है। जिससे दोनों ओर छोटे व्यापारियों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के नेपाल सीमा से सटे जिलों में अब इस नई नीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। नेपाल द्वारा सख्ती बढ़ाए जाने के बाद भारत से नेपाल जाने वाले रोजमर्रा के सम्मान जैसे दाल, चीनी, रिफाइंड, तेल, कपड़े आदि की कीमत से 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। जबकि बिक्री 15 से 25% तक घट गई है। यूपी का सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सनौली जैसे इलाकों में दुकानों की बिक्री 15 से 25% तक घट गई है। वहीं बिहार के बघार, रक्कसोल और जयनगर जैसे बाजारों में यह गिरावट 50% तक पहुंच गई है। इन बाजारों का बड़ा हिस्सा नेपाली ग्राहकों पर निर्भर है। ऐसे में छोटे दुकानदारों के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है। नेपाल के कई इलाके खासकर वीरगंज और आसपास के क्षेत्रों में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों और संगठनों का कहना है कि नेपाल भारत के बीच सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। जिसमें सीमाओं के बावजूद लोगों का आना-जाना और व्यापार सहज रहा है। लोगों का आरोप है कि अब कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और बिस्किट जैसे छोटे सामानों को ले जाने पर भी नेपाली सशस्त्र पुलिस द्वारा वसूली या जब्ती की जा रही है। जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है।

अभियान

भोर का रहस्य: क्यों कहते हैं बड़े-बुजुर्ग “सुबह जागो, भाग्य जागेगा”

भारतीय परिवारों में अक्सर दादी-नानी की एक बात बचपन से सुनने को मिलती है—“उठ जा, वरना भाग्य सोता रह जाएगा।” यह वाक्य केवल एक घरेलू सलाह नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, परंपरा और जीवन दर्शन का निचोड़ है। खासकर सुबह के उस समय को, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले का होता है, यानी लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। इस समय को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है।

प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर Ayurveda, में ब्रह्म मुहूर्त को जीवन के संतुलन का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे शांत, शुद्ध और संतुलित रूप में होती है। रात का अंधकार समाप्त होने की ओर होता है और दिन का प्रकाश धीरे-धीरे फैलने लगता है। इस संक्रमण काल में वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो मनुष्य के शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है।

जब व्यक्ति इस समय उठता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। दिनभर के शोर-शराबे, काम के दबाव और डिजिटल व्यस्तता से पहले का यह समय मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि-मुनि इस समय ध्यान, साधना और अध्ययन करते थे। आज के आधुनिक जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति इस समय का उपयोग ध्यान, प्राणायाम या योग के लिए करता है, तो उसका मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। यह समय आत्मचिंतन का भी होता है, जब व्यक्ति अपने जीवन, लक्ष्य और विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुबह जल्दी उठने के कई लाभ हैं। इस समय वातावरण में प्रदूषण कम होता है और हवा अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ होती है। ताजी हवा में सांस लेने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर के सभी अंग बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। यही कारण है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वे अपने कार्यों में अधिक सक्रिय और उत्पादक पाए जाते हैं। इसके अलावा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सीधा संबंध हमारे शरीर की जैविक घड़ी से भी है। मानव शरीर एक निश्चित लय में कार्य करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। जब हम इस प्राकृतिक लय के अनुसार सोते और जागते हैं, तो हमारा शरीर संतुलित रहता है। सुबह जल्दी उठने से पाचन तंत्र बेहतर कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर पूरे दिन बना रहता है। इसके विपरीत, देर तक सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और दिनभर सुस्ती महसूस होती है।

भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक उन्नति का भी सबसे उपयुक्त समय माना गया है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया से जुड़ सकता है। इस समय किया गया जप, ध्यान या प्रार्थना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि मन उस समय पूरी तरह शांत और एकाग्र होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा और चेतना शुद्ध होती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। यदि इस समय घर की खिड़कियां खोली जाएं, दीपक जलाया जाए या हल्का संगीत या मंत्र उच्चारण किया जाए, तो घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि घर में एक सुखद और संतुलित ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है।

बड़े-बुजुर्ग यह भी मानते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसके जीवन में अनुशासन और स्थिरता आती है। यह आदत धीरे-धीरे व्यक्ति के पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देती है। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होती है, तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है, तनाव कम महसूस करता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है।

इसके साथ ही, सुबह का समय सीखने और रचनात्मक कार्यों के लिए भी सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय मस्तिष्क ताजा और सक्रिय होता है, जिससे नई चीजें जल्दी समझ में आती हैं। विद्यार्थी यदि इस समय पढ़ाई करें, तो उनकी एकाग्रता और याददाश्त दोनों में सुधार होता है। यही कारण है कि पुराने समय में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करने की परंपरा थी।

दादी-नानी की यह सलाह केवल परंपरा का पालन भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन मंत्र है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। आज के समय में, जब लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तब यह परंपरा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय हो सकता है।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि इस आदत को धीरे-धीरे अपनाया जाए। अचानक बहुत जल्दी उठने की कोशिश करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले अपनी नींद की दिनचर्या को सुधारना आवश्यक है, ताकि शरीर को पर्याप्त आराम मिल सके। जब शरीर पूरी तरह से विश्राम करता है, तभी सुबह जल्दी उठना वास्तव में लाभकारी होता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक धार्मिक या पारंपरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक जीवनशैली का हिस्सा है। यह आदत व्यक्ति को न केवल स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है, बल्कि उसे जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और सफलता की ओर भी अग्रसर करती है। दादी-नानी की यह सरल सी बात कि “सुबह उठो, वरना भाग्य सो जाएगा” वास्तव में जीवन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत सही समय और सही ऊर्जा के साथ करते हैं, तो हमारा भाग्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है, और यही जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार बनता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सूरत की सियासत में शक्ति प्रदर्शन: पाटीदार इलाकों में सीएम भूपेंद्र पटेल का मेगा रोड शो, चुनावी माहौल गरमाया

सूरत की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ढोल-नगाड़ों और चुनावी नारों की गूंज, और हर तरफ भगवा रंग में रंगा माहौल—स्थानीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में शहर ने जिस राजनीतिक ऊर्जा को देखा, वह लंबे समय तक याद रखी जाएगी। Bhupendra Patel के नेतृत्व में निकला यह मेगा रोड शो केवल एक चुनावी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उस राजनीतिक आत्मविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके सहारे Bharatiya Janata Party सूरत नगर निगम में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

यह रोड शो सीमाडा नाका से शुरू होकर हीराबाग सर्कल तक पहुंचा, लेकिन इसके प्रभाव की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोग, छतों और बालकनियों पर जमा भीड़, और हर कुछ मीटर पर रुककर हाथ हिलाते मुख्यमंत्री—यह दृश्य किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। मुख्यमंत्री जिस विशेष वाहन में सवार थे, उसे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सजावट के मेल से तैयार किया गया था। वाहन पर Narendra Modi की तस्वीरें प्रमुखता से लगी थीं, जो यह संकेत दे रही थीं कि यह चुनाव केवल स्थानीय नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

रोड शो का मार्ग अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था। नाना वराछा की ढलान से शुरू होकर यह यात्रा शहर के उन इलाकों से गुजरी, जहां पाटीदार समुदाय का प्रभाव सबसे अधिक है। वार्ड नंबर 3 का चुनाव कार्यालय, चिकुवाड़ी सीएनजी पंप, मारुति सुजुकी शोरूम, बाप्स मंदिर कापोद्रा, पीपी मनिया हॉस्पिटल, कापोद्रा पुलिस स्टेशन, वार्ड नंबर 4 कार्यालय और अंत में हीराबाग सर्कल—हर पड़ाव पर भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था।

इस रोड शो की एक खास बात यह रही कि इसमें केवल पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी भी अभूतपूर्व रही। सूरत का हीरा और टेक्सटाइल उद्योग देशभर में प्रसिद्ध है, और इस उद्योग से जुड़े हजारों कारीगर अपने काम को छोड़कर इस आयोजन का हिस्सा बने। कई जगहों पर फैक्ट्रियों के बाहर कारीगर अस्थायी मंच बनाकर या सीढ़ियों पर चढ़कर मुख्यमंत्री को देखने की कोशिश करते नजर आए। यह दृश्य इस बात का संकेत था कि राजनीतिक कार्यक्रम किस तरह समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर सकता है।

जैसे-जैसे रोड शो आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे माहौल और अधिक उत्साहपूर्ण होता गया। डीजे और साउंड सिस्टम पर बजते गीतों ने पूरे क्षेत्र को एक उत्सव में बदल दिया। "आएगी तो भाजपा ही" जैसे नारों की गूंज ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के मन में विश्वास और एकजुटता का भाव पैदा करना था।

सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण था। हजारों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरे मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी। जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी और सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे। रोड शो के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता।

धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों की भागीदारी ने इस आयोजन को एक अलग आयाम दिया। ब्रह्मो समाज और संतों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें तलवार, श्रीमद् भगवद गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। यह दृश्य न केवल सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीति और समाज के विभिन्न आयाम किस तरह एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

रोड शो के दौरान एक दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला जब यह यात्रा अस्पताल क्षेत्र से गुजरी। वहां काम में व्यस्त डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी अपने काम के बीच समय निकालकर इस आयोजन को देखने लगे। कई लोग बालकनी और खिड़कियों से झांकते हुए मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। यह दिखाता है कि इस तरह के राजनीतिक आयोजन समाज के हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह रोड शो केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। पाटीदार समुदाय गुजरात की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में इस समुदाय के क्षेत्रों में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन यह संकेत देता है कि भाजपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसके साथ ही, यह रोड शो विपक्ष के लिए भी एक संदेश है। जहां एक ओर भाजपा अपने संगठन और संसाधनों के दम पर बड़े आयोजन कर रही है, वहीं विपक्ष को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि, विपक्ष ने इस रोड शो को लेकर अपनी आलोचना भी की है और इसे केवल दिखावा बताया है, लेकिन भीड़ की संख्या और उत्साह को नजरअंदाज करना आसान नहीं है।

स्थानीय निकाय चुनाव का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह सीधे तौर पर शहर के विकास से जुड़ा होता है। सड़कों, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर नगर निगम का सीधा नियंत्रण होता है। ऐसे में यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। Bharatiya Janata Party ने इस रोड शो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह विकास और सुशासन के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं Narendra Modi की तस्वीरों का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को भी स्थानीय स्तर पर भुनाना चाहती है।

सूरत, जो देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहरों में से एक है, वहां का राजनीतिक माहौल हमेशा से ही खास रहा है। यहां के मतदाता विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, और यही कारण है कि चुनावी रणनीतियां भी इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमती हैं।

इस रोड शो के बाद यह साफ हो गया है कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के दम पर आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में और भी रैलियां, जनसभाएं और रोड शो देखने को मिल सकते हैं, जो चुनावी माहौल को और अधिक गर्माएंगे।

अंततः, यह रोड शो केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हर दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करता है। सूरत की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

अब सबकी नजरें मतदान के दिन और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस शक्ति प्रदर्शन का असर वोटों में कितना बदलता है और सूरत नगर निगम में किसका परचम लहराता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस रोड शो ने सूरत की सियासत को नई दिशा और नई ऊर्जा दे दी है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

वैश्विक दबाव में ध्वस्त हुआ बाजार: सेंसेक्स 852 अंक टूटा, निवेशकों की संपत्ति में 2.99 लाख करोड़ की बड़ी सेंध

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आई तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते बाजार पर दबाव साफ दिखाई दिया। कारोबारी सत्र के अंत में BSE Sensex 852.49 अंक यानी 1.09% गिरकर 77,664 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि NSE Nifty 205.05 अंक यानी 0.84% टूटकर 24,173.05 पर आ गया। दिनभर का कारोबार उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन बाजार की दिशा स्पष्ट रूप से नकारात्मक रही। शुरुआती गिरावट के बाद कुछ समय के लिए खरीदारी का हल्का रुझान दिखा, जिससे ऐसा लगा कि बाजार संभल सकता है, लेकिन यह तेजी टिक नहीं सकी। सुबह करीब 10 बजे के बाद बिकवाली का दबाव तेज हो गया और निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली शुरू कर दी। इसका असर यह हुआ कि सेंसेक्स दिन के दौरान 942 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 243 अंक तक नीचे चला गया।

हालांकि अंतिम घंटे में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वह नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों प्रमुख सूचकांक आखिरकार नुकसान के साथ बंद हुए, जिससे बाजार का मूड स्पष्ट रूप से कमजोर बना रहा।

इस गिरावट का सबसे बड़ा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। Bombay Stock Exchange में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर 466.37 लाख करोड़ रह गया, जो पिछले सत्र के 469.36 लाख करोड़ के मुकाबले लगभग 2.99 लाख करोड़ की गिरावट दर्शाता है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि बाजार में आई गिरावट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि व्यापक निवेशक विश्वास पर असर डालने वाली है।

सेक्टोरल स्तर पर भी लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में दबाव देखा गया। ऑटो, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, एफएमसीजी, मेटल और ऑयल-गैस सेक्टर में भारी बिकवाली हुई। ये सेक्टर आमतौर पर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनमें आई कमजोरी ने समग्र बाजार को नीचे खींचा। दूसरी ओर, मीडिया, एनर्जी, कैपिटल गुड्स और हेल्थकेयर सेक्टर में सीमित खरीदारी जरूर देखने को मिली, लेकिन यह सकारात्मकता व्यापक गिरावट को रोकने में नाकाफी रही।

ब्रॉडर मार्केट की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं रही। मिडकैप इंडेक्स 0.41% और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.67% गिरा, जो यह दर्शाता है कि दबाव केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे और मध्यम वर्ग के शेयरों में भी बिकवाली का माहौल बना रहा।

मार्केट ब्रेड्थ यानी बाजार में बढ़त और गिरावट वाले शेयरों का अनुपात भी कमजोर रहा। बीएसई पर कुल 4,449 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,517 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि केवल 1,762 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इसी तरह, एनएसई पर 2,965 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें 1,934 शेयर लाल निशान में और 1,031 शेयर हरे निशान में बंद हुए। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बाजार में बिकवाली का दबाव व्यापक और गहरा था।

अगर प्रमुख शेयरों की बात करें तो कुछ कंपनियों ने गिरते बाजार में भी मजबूती दिखाई। टॉप गेनर्स में Dr. Reddy's Laboratories 9.37% की तेजी के साथ सबसे आगे रहा। इसके अलावा Cipla 5.63%, Jio Financial Services 4.26%, Adani Enterprises 1.73% और Apollo Hospitals 1.55% की बढ़त के साथ बंद हुए। इन कंपनियों में आई तेजी यह दर्शाती है कि बाजार में चुनिंदा खरीदारी अभी भी जारी है, खासकर डिफेंसिव और हेल्थकेयर सेक्टर में।

वहीं दूसरी ओर, कई दिग्गज शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स में Trent 4.13% टूटकर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। इसके अलावा Shriram Finance 3.37%, Mahindra & Mahindra 3.24%, SBI Life Insurance 3.01% और Tech Mahindra 2.81% की गिरावट के साथ बंद हुए। इन शेयरों में आई कमजोरी ने बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनाया। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है, जो भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए चिंता का विषय बन जाती है।

गर्मी की भीड़ पर काबू के लिए बड़ा कदम: पश्चिम रेलवे की स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को राहत

वडोदरा से आई एक महत्वपूर्ण खबर ने हजारों यात्रियों को राहत की सांस दी है। बढ़ती गर्मी, छुट्टियों के सीजन और अचानक बढ़ी यात्रा मांग के बीच Western Railway ने विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है और यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

Western Railway के जनसंपर्क अधिकारी Anubhav Saxena द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ये स्पेशल ट्रेनें सीमित फेरों के लिए विशेष किराए पर चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकें। इन ट्रेनों का संचालन पश्चिम भारत से पूर्वी और मध्य भारत के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और परिवारों को यात्रा में सुविधा मिल सके।

सबसे पहले वलसाड–खड़गपुर स्पेशल ट्रेन (संख्या 09043/09044) की बात करें तो यह 26 अप्रैल 2026 को वलसाड से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 21:00 बजे खड़गपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 28 अप्रैल को सुबह 05:00 बजे खड़गपुर से चलकर अगले दिन दोपहर 15:30 बजे वलसाड पहुंचेगी। इस ट्रेन का रूट काफी व्यापक है और यह भेस्तान, नंदुरबार, भुसावल, नागपुर, रायपुर, राउरकेला और टाटानगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी। इसमें एसी थर्ड क्लास, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा दी गई है, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखा गया है।

दूसरी अहम ट्रेन उधना–मालदा टाउन स्पेशल (09013/09014) है, जो 28 अप्रैल को उधना से दोपहर 14:30 बजे रवाना होकर 30 अप्रैल को सुबह 05:10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। वापसी यात्रा उसी दिन सुबह 08:10 बजे शुरू होकर रात 23:45 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन इटारसी, जबलपुर, पटना और भागलपुर जैसे प्रमुख जंक्शनों से होकर गुजरेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

इसके अलावा, यात्रियों के लिए एक विशेष वातानुकूलित विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। उधना–मालदा टाउन एसी स्पेशल (09063/09064) 27 अप्रैल को रात 20:15 बजे उधना से रवाना होकर 29 अप्रैल को 11:30 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। वापसी में यह 29 अप्रैल को शाम 17:35 बजे चलकर 1 मई को सुबह 10:00 बजे उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन में 3-टियर एसी कोच की सुविधा होगी, जो लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक सफर का विकल्प प्रदान करेगी।

सामान्य यात्रियों और बिना आरक्षण यात्रा करने वालों के लिए भी रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। उधना–मधुबनी अनारक्षित स्पेशल (09167/09168) 23 और 26 अप्रैल को सुबह 05:30 बजे उधना से रवाना होकर अगले दिन शाम 19:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 24 और 27 अप्रैल को रात 22:00 बजे मधुबनी से चलकर अगले दिन 11:35 बजे उधना पहुंचेगी। यह पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन होगी, जिससे तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसी कड़ी में उधना–समस्तीपुर अनारक्षित स्पेशल (09069/09070) का संचालन भी किया जा रहा है, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विभिन्न दिनों में उधना से सुबह 05:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 16:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 25 अप्रैल से 1 मई के बीच समस्तीपुर से रात 19:00 बजे चलकर उधना पहुंचेगी। इसमें स्लीपर और सेकेंड क्लास कोच की सुविधा दी गई है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा।

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन संख्या 09063, 09013 और 09043 के लिए बुकिंग 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसे यात्री IRCTC की वेबसाइट या नजदीकी पीआरएस काउंटर से कर सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी, ठहराव और अन्य जरूरी जानकारियां आधिकारिक स्रोत से अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्पेशल ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रियों के दबाव को कम करता है, बल्कि रेलवे नेटवर्क के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करता है। खासकर त्योहारों, छुट्टियों और परीक्षा सत्र के दौरान इस तरह की पहल बेहद जरूरी हो जाती है।

कुल मिलाकर, Western Railway का यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि भीड़भाड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में यदि मांग और बढ़ती है, तो रेलवे द्वारा और भी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सोना वायदा में 642 रुपये और चांदी वायदा में 6083 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा में 93 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 256639.12 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26905.15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 229733.96 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2629.7 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17271.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 152051 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152543 रुपये और नीचे में 151451 रुपये पर पहुंचकर, 152657 रुपये के पिछले बंद के सामने 642 रुपये या 0.42 फीसदी घटकर 152015 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 461 रुपये या 0.38 फीसदी औंधकर 121424 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 56 रुपये या 0.37 फीसदी घटकर 15221 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 150701 रुपये के भाव पर खूलकर, 151080 रुपये के दिन के उच्च और 150063 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 618 रुपये या 0.41 फीसदी गिरकर 150597 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 150652 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151211 रुपये और नीचे में 150128 रुपये पर पहुंचकर, 151390 रुपये के पिछले बंद के सामने 643 रुपये या 0.42 फीसदी घटकर 150747 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 242501 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 244730 रुपये और नीचे में 239600 रुपये पर पहुंचकर, 248364 रुपये के पिछले बंद के सामने 6083 रुपये या 2.45 फीसदी घटकर 242281 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 5937 रुपये या 2.37 फीसदी लुढ़ककर 244407 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 5935 रुपये या 2.37 फीसदी गिरकर 244479 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 4297.52 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 5.55 रुपये या 0.43 फीसदी गिरकर 1277.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 75 पैसे या 0.21 फीसदी की नरमी के साथ 348.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 35 पैसे या 0.09 फीसदी की नरमी के साथ 372.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी घटकर 196.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 26905.15 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 229733.96 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 17271.17 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4926.47 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8799 रुपये के भाव पर खूलकर, 9026 रुपये के दिन के उच्च और 8791 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 93 रुपये या 1.07 फीसदी की तेजी के संग 8816 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 93 रुपये या 1.07 फीसदी की तेजी के संग 8817 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 255.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 257.3 रुपये और नीचे में 254.8 रुपये पर पहुंचकर, 255.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 70 पैसे या 0.27 फीसदी बढ़कर 256.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 80 पैसे या 0.31 फीसदी चढ़कर 256.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 998 रुपये पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी टूटकर 999.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7620.69 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9650.47 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3520.21 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 394.38 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 11.07 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 366.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3845.08 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1065.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.93 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9828 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61202 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28919 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 392994 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65679 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9185 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 26520 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 100568 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14635 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 34546 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 20.9 रुपये की बढ़त के साथ 663 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.2 रुपये की गिरावट के साथ 0.5 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 167 रुपये की गिरावट के साथ 817 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1941 रुपये की गिरावट के साथ 705 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.99 रुपये की गिरावट के साथ 2.84 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 97 पैसे के सुधार के साथ 3.3 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 5.2 रुपये की गिरावट के साथ 367.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.75 रुपये की गिरावट के साथ 1.05 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 32.5 रुपये की बढ़त के साथ 400.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 68.5 रुपये की बढ़त के साथ 288.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की गिरावट के साथ 0.97 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 18 पैसे की नरमी के साथ 0.01

डिंडोली में 'आयरन सिंडिकेट' का भंडाफोड़: 60 टन चोरी की टीएमटी रॉड बरामद, एसओजी की रेड में चार दबोचे

सूरत। शहर के तेजी से बढ़ते निर्माण कारोबार के बीच चोरी के एक संगठित रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। Surat City Special Operations Group ने डिंडोली इलाके में सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 60 टन चोरी की टीएमटी रॉड के साथ चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई न केवल मात्रा के लिहाज से बड़ी है, बल्कि इससे उस संगठित नेटवर्क की झलक भी मिलती है जो ट्रांसपोर्ट चेन के भीतर सेंध लगाकर करोड़ों का माल गायब कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, भाग्यलक्ष्मी सोसाइटी के पास की गई इस रेड में कुल 59,910 किलोग्राम लोहे की रॉड बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 32.95 लाख रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही एक ट्रेलर (करीब 33 लाख रुपये), एक चार पहिया वाहन (लगभग 5 लाख रुपये), मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई। कुल मिलाकर करीब 71.52 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस के कब्जे में आई है। यह बरामदगी बताती है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर माल खपाने की क्षमता रखता था।

गिरफ्तार आरोपियों में भेराराम रेखाराम जाखड़ और निम्बाराम बाबूलाल जाखड़—दोनों बाड़मेर (राजस्थान) के निवासी—ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के रूप में काम करते थे। इनके साथ डिंडोली में रहने वाले प्रदीप सदाबृज त्रिपाठी (मूल निवासी उत्तर प्रदेश) और प्रदीप किशनलाल शर्मा (मूल निवासी राजस्थान) को भी दबोचा गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी मिलकर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल में हेरफेर कर बड़ी मात्रा में रॉड निकाल लेते थे और फिर उसे सस्ते दामों पर स्थानीय बाजार में खपाने की कोशिश करते थे।

जांच में जो तरीका सामने आया है, वह बेहद सुनियोजित है। ट्रक में लदी खेप के कागज

सही रहते थे, लेकिन रास्ते में या गंतव्य से पहले तय स्थानों पर माल का एक हिस्सा उतार लिया जाता था। इसके बाद शेष माल को नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता, जिससे पहली नजर में किसी तरह की कमी पकड़ में न आए। इस तरह छोटे-छोटे हिस्सों में की गई चोरी समय के साथ बड़ी मात्रा में बदल जाती थी। पुलिस का मानना है कि इस तरीके से कई बार वारदातें की गई होंगी।

इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, यह 'लाइव रेड' थी—यानी जैसे ही गिरोह माल खपाने की कोशिश में सक्रिय हुआ, टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। Rajdeepsinh Nakum ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह इनपुट-आधारित थी और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ना इस बात का सबूत है कि पुलिस ने लंबे समय से इस नेटवर्क पर नजर रखी हुई थी।

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के पीछे दो कथित मास्टरमाइंड—जीतू और राजन तिवारी—हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इनके पकड़े जाने के बाद इस रैकेट के और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट चेन के अन्य लोग या बिचौलिए शामिल हो सकते हैं।

मामले का एक अहम पहलू चोरी के माल की 'डिमांड साइड' है—यानी यह रॉड किन-किन खरीदारों तक पहुंचाई जा रही थी। निर्माण क्षेत्र में टीएमटी रॉड की लगातार मांग रहती है, और कम कीमत पर मिलने वाला माल कई बार बिना पर्याप्त जांच के खरीद लिया जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई व्यापारी, बिल्डर या सप्लायर इस चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चारों आरोपियों के खिलाफ डिंडोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिमांड लेकर उनसे गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि पिछले मामलों, अन्य सहयोगियों और सप्लाई चैन की पूरी कड़ी को सामने लाया जा सके। यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस गिरोह का संबंध अन्य शहरों या राज्यों में सक्रिय नेटवर्क से तो नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण सामग्री की चोरी का यह पैटर्न नया नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ पकड़ी गई खेप इस बात का संकेत है कि निगरानी और सत्यापन तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों, गोदाम संचालकों और खरीदारों के बीच बेहतर समन्वय और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे अपराधों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

फिलहाल, सूरत पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे न केवल करोड़ों रुपये के नुकसान को रोका गया है, बल्कि उन संगठित गिरोहों को भी स्पष्ट संदेश गया है जो सप्लाई चेन में सेंध लगाकर अवैध कमाई करते हैं। आने वाले दिनों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की जांच इस पूरे मामले को और स्पष्ट करेगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि 'आयरन सिंडिकेट' की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए किन-किन स्तरों पर कार्रवाई की जरूरत है।

तेल के तूफान और वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार पर दबाव, HSBC ने घटाई रेटिंग

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तेजी से बदलते संकेतों के बीच अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था HSBC ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपना रुख और अधिक सतर्क कर लिया है। लगातार दूसरी बार रेटिंग में कटौती करते हुए HSBC ने इंडियन इक्विटीज को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' कर दिया है। इससे पहले 31 मार्च को ही फर्म ने इसे 'ओवरवेट' से 'न्यूट्रल' किया था। यानी एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी गिरावट है, जो बाजार के प्रति बढ़ती चिंताओं को साफ तौर पर दर्शाती है।

इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल बताया जा रहा है। Brent Crude की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है और हाल के महीनों में इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इससे न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि कंपनियों के मुनाफे पर भी सीधा असर पड़ता है।

HSBC की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। NSE Nifty और BSE Sensex जैसे प्रमुख सूचकांकों में हालिया गिरावट ने निवेशकों की चिंता को और गहरा कर दिया है। निफ्टी जहां करीब 6.7 प्रतिशत तक गिर चुका है, वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 7.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट भारत को उन प्रमुख बाजारों की सूची में शामिल कर रही है, जहां हाल के समय में प्रदर्शन कमजोर रहा है। विदेशी निवेशकों की भूमिका भी इस गिरावट में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा करीब 18.5 अरब डॉलर की शुद्ध बिकवाली की गई है। यह आंकड़ा न केवल निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है, बल्कि रुपये पर भी दबाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। जब विदेशी निवेशक लगातार पूंजी निकालते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पर बाजार की तरलता और स्थिरता पर पड़ता है।

HSBC ने अपनी रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया है—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। रिपोर्ट के अनुसार, AI के बढ़ते उपयोग से आईटी सेवाओं के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है। भारत का आईटी सेक्टर लंबे समय से वैश्विक सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन नई तकनीकों के चलते इस सेक्टर की आय में अनिश्चितता बढ़ सकती है। यह स्थिति निवेशकों के लिए एक नया जोखिम पैदा करती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। HSBC का अनुमान है कि जून और सितंबर तिमाही के दौरान ऊर्जा आपूर्ति में तंगी बनी रह सकती है। इसका सीधा असर कंपनियों की लागत और मुनाफे पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस कारण भारत की अर्निंग ग्रोथ में करीब 1.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन बड़े पैमाने पर यह बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

बाजार के मूल्यांकन (Valuation) को लेकर भी HSBC ने चिंता जताई है। हालिया गिरावट के बावजूद, यदि कंपनियों की कमाई के अनुमान और घटते हैं, तो मौजूदा वैल्यूएशन भी महंगे साबित हो सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि कीमतों में और गिरावट की संभावना बनी रहती है।

विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशी निवेशकों का रुख और तकनीकी बदलाव—ये सभी कारक मिलकर बाजार की दिशा तय करेंगे। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने और सोच-समझकर निवेश करने का है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट अवसर भी बन सकती है। जब बाजार दबाव में होता है, तब मजबूत कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, HSBC की यह रेटिंग कटौती केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में निवेशकों को हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

2,800 करोड़ का दांव: भारत में ई-कॉमर्स की रफ्तार बढ़ाने उतरा अमेजन, एआई और कर्मचारियों पर बड़ा फोकस

नई दिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए Amazon India ने 2,800 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह निवेश सिर्फ एक कारोबारी विस्तार नहीं, बल्कि देश में ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी ने साफ किया है कि यह राशि ऑपरेशंस नेटवर्क के विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटलीकरण और कर्मचारियों के समग्र कल्याण पर खर्च की जाएगी।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल उपभोक्ता बाजारों में शामिल हो चुका है। कंपनी की दीर्घकालिक योजना के तहत 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, और मौजूदा 2,800 करोड़ उसी बड़े विज़न की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अमेजन भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देख रहा है।

कंपनी के मुताबिक, इस निवेश का बड़ा हिस्सा एआई-आधारित टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में लगाया जाएगा। इससे सप्लाई चेन को अधिक स्मार्ट, तेज और कुशल बनाया जाएगा। ग्राहकों के ऑर्डर को समझने, डिमांड का अनुमान लगाने और डिलीवरी को समयबद्ध बनाने में एआई अहम भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में ग्राहक कुछ ही मिनटों या

घंटों में अपने उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे, जो ई-कॉमर्स अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है।

लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। कंपनी अपने फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्टेशन हब और लास्ट-माइल डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत करेगी। इसका सीधा फायदा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा, जहां अब तक तेज डिलीवरी एक चुनौती बनी हुई थी। यह विस्तार न केवल ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और विक्रेताओं को भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेगा।

क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी अमेजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी की सेवा 'Amazon Now' पहले ही प्रमुख शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और अब इसे और विस्तार देने की योजना है। वर्तमान में 300 से अधिक माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर के जरिए यह सेवा ग्राहकों तक तेज डिलीवरी सुनिश्चित कर रही है। नए निवेश के बाद यह नेटवर्क और व्यापक होगा, जिससे मिनटों में डिलीवरी का सपना और करीब आएगा।

कर्मचारी कल्याण इस निवेश का एक अहम स्तंभ है। अमेजन ने 'प्रोजेक्ट आश्रय' के तहत अपने कर्मचारियों और उनसे जुड़े समुदायों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें अब और विस्तार दिया जाएगा। कंपनी मेडिकल और दुर्घटना बीमा को मजबूत करेगी, साथ ही हजारों कर्मचारियों और 2 लाख से अधिक सामुदायिक सदस्यों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल केवल कॉर्पोरेट जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक स्थायी और समावेशी विकास मॉडल की ओर इशारा करती है।

यह पहला मौका नहीं है जब अमेजन ने भारत में इतना बड़ा निवेश किया हो। वर्ष 2025 में भी कंपनी ने 2,000 करोड़ का निवेश किया था, जिसके तहत देशभर में 17 फुलफिलमेंट सेंटर, 6 सॉर्टेशन सेंटर और 75 लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन स्थापित किए गए थे। इन प्रयासों ने पहले ही डिलीवरी समय को कम करने और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अमेजन का यह नया निवेश भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को और तेज करेगा। इससे अन्य कंपनियां भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी। नतीजतन, पूरे सेक्टर में नवाचार, रोजगार सृजन और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा।

हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लॉजिस्टिक्स लागत, अंतिम मील की डिलीवरी की जटिलताएं और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाना अब भी कठिन कार्य हैं। इसके अलावा, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता गोपनीयता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन अमेजन का यह निवेश यह संकेत देता है कि कंपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कुल मिलाकर, 2,800 करोड़ का यह निवेश केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल और ई-कॉमर्स भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में इसका असर न केवल ग्राहकों के अनुभव पर पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी विकास पर भी गहराई से दिखाई देगा।

बेटियों ने रचा इतिहास: यूपी बोर्ड 2026 में टॉपर्स पर बेटियों का कब्जा, सीतापुर बना शिक्षा का नया सितारा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी परीक्षा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) वर्ष 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार का रिजल्ट केवल अंकों का आंकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और बेटियों की बढ़ती ताकत की कहानी बनकर सामने आया है। करीब 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था और अब उनके सपनों को दिशा देने वाला यह परिणाम सार्वजनिक हो चुका है।

इस वर्ष की सबसे खास बात यह रही कि मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दिया। टॉप-11 में से 10 स्थान बेटियों ने अपने नाम किए, जो न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि समाज में बदलती सोच और शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी प्रमाण है। यह परिणाम उन परिवारों के लिए भी प्रेरणा है, जो अब बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे हैं।

हाईस्कूल परीक्षा में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। दूसरे स्थान पर अदिति ने 97.50 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि तीसरे स्थान

पर अर्पिता, ऋषभ साहू और परी वर्मा ने 97.33 प्रतिशत अंक के साथ अपनी जगह बनाई। इस सूची में भी बेटियों की संख्या अधिक रही, जो एक सकारात्मक संकेत है।

इंटरमीडिएट की बात करें तो यहां भी बेटियों का ही परचम लहराया। सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद नंदिनी गुप्ता और श्रेया वर्मा ने 97.20 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर सुरभि यादव और पूजा पाल ने 97.00 प्रतिशत अंक हासिल किए। इस पूरी सूची में लड़कियों का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता है।

इस बार के परिणामों में एक और खास बात सामने आई, वह है सीतापुर जिले का शानदार प्रदर्शन। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट—दोनों परीक्षाओं में इस जिले के छात्रों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे यह संकेत मिलता है कि छोटे शहरों और जिलों में भी शिक्षा का स्तर तेजी से सुधर रहा है और वहां के छात्र अब बड़े शहरों के छात्रों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सीतापुर का यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बन गया है।

रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के बीच उत्साह और भावनाओं का माहौल देखने को मिला। जहां एक ओर टॉपर्स के घरों में जश्न का माहौल है, वहीं कई छात्र अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता से सोचने में जुट गए हैं। यह परिणाम उनके करियर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। छात्र अपने परिणाम upmsp.edu.in और digilocker.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे विषयवार अंक और कुल प्रतिशत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध अंकपत्र को फिलहाल प्रोविजनल माना जाएगा, जबकि मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगी। DigiLocker के माध्यम से डाउनलोड की गई मार्कशीट भी आधिकारिक रूप से मान्य है, जिससे छात्रों को किसी भी प्रक्रिया में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस वर्ष के परिणाम ने यह भी दिखाया है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग अब शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट की सुविधा ने छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के परिणाम समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, तो वह पूरे समाज को प्रेरित करती हैं। यह न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है, बल्कि देश के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, यूपी बोर्ड 2026 का यह परिणाम केवल एक परीक्षा का निष्कर्ष नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है, जहां बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं। आने वाले समय में यही छात्र-छात्राएं देश के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

पश्चिम रेलवे चलाएगी गांधीधाम-मालदा टाउन–गांधीधाम समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम–मालदा टाउन–गांधीधाम के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रेन संख्या 09463/09464 गांधीधाम-मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल

- ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम-मालदा टाउन समर स्पेशल दिनांक 25 अप्रैल 2026 (शनिवार) को गांधीधाम से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सोमवार को 09:10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी।
- इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09464 मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल दिनांक 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को मालदा टाउन से 17:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन बुधवार को 15:30 बजे गांधीधाम पहुंचेगी।
- यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में सामाखियाली, राधनपुर, भीलड़ी, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना, किउल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बड़हरवा और न्यू फरक्का स्टेशनों पर रुकेगी।
- इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम – मालदा टाउन समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 24 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

- ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09435/09436 साबरमती–आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (विशेष किराये पर) चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 29 अप्रैल 2026 को साबरमती से 22:55 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 14:30 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09436 आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 01 मई 2026 को आसनसोल से 16:15 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, इडगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा तथा धनबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 24 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

जग्गी हत्याकांड में बड़ा मोड़: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को अंतरिम राहत, उम्रकैद पर लगी रोक

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने रामअवतार जग्गी हत्याकांड में एक अहम मोड़ आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने पूर्व विधायक Amit Jogi को अंतरिम राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले ने न केवल मामले की दिशा बदल दी है, बल्कि कानूनी बहस को भी नए सिरे से तेज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि फिलहाल सजा के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी और जोगी को 23 अप्रैल तक सरेंडर करने के निर्देश को भी स्थगित किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने Central Bureau of Investigation से जवाब तलब किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपील और दोषसिद्धि की प्रक्रिया में किन आधारों पर निर्णय लिए गए थे। यह आदेश इस बात का संकेत है कि अदालत मामले के हर पहलू को गहराई से परखना चाहती है।

सुनवाई के दौरान जोगी पक्ष के वरिष्ठ वकीलों ने दो अहम बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, सीबीआई को अपील की अनुमति देने के आदेश की वैधता, और दूसरा, हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि का आधार। बचाव पक्ष का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में जोगी को बरी किया था, ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला कई कानूनी सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक स्तर पर राहत देना उचित समझा।

यह मामला लगभग दो दशक पुराना है, जिसकी जड़ें 4 जून 2003 की उस घटना से जुड़ी हैं, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता Ramavatar Jaggi की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह घटना एक बड़ा झटका मानी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच राज्य पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसने विस्तृत जांच के बाद अमित जोगी समेत कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान 31 मई 2007 को ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला उस समय काफी चर्चा में रहा था। हालांकि, बाद में सीबीआई की अपील पर Chhattisgarh High Court ने मामले की दोबारा सुनवाई की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को भी दोषी करार दे दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 23 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें अब अंतरिम राहत मिली है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह राहत अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सुरक्षा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम सुनवाई तक आरोपी को तुरंत सजा का सामना न करना पड़े। अदालत अब सीबीआई के जवाब और दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के आधार पर आगे का फैसला करेगी।